

लोक शिकायत एवं निराकरण संगोष्ठी व राष्ट्र गौरव सम्मान समारोह

CENTRAL PUBLIC GRIEVANCES &
INVESTIGATION INSTITUTION



वर्ष 2022

आपकी समस्या का समाधान, हमारा कर्तव्य

केन्द्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान

स्वतंत्रता एवं न्याय प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार



- गोपाल राय
चेयरमैन
केन्द्रीय लोक शिकायत
एवं जांच संस्थान



भ्रष्टाचार एवं अन्याय के खिलाफ लड़ाई ही मूल मकसद - गोपाल राय

प्रशासनिक कार्यालय : 65/25, छितवापुर रोड, लालकुआँ, लखनऊ- 226 0 01 फोन : 0522-2637228, 9956016175
नई दिल्ली कार्यालय: 2392, तिलक गली, पहाड़गंज, नई दिल्ली- 110 055, मोबाइल: 9450776737

✉ www.cpgii.org | 📩 chairman.cpgi@gmail.com



गोपाल राय

चेयरमैन

केन्द्रीय लोक शिकायत
एवं जांच संस्थान

भ्रष्टाचार एवं अन्याय के खिलाफ लड़ाई ही मूल मकसद - गोपाल राय

केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान के नेशनल चेयरमैन गोपाल राय ने कहा कि संस्थान सम्पूर्ण भारत के सभी प्रदेशों में स्टेट एवं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का गठन एक माह के अंदर कर समाज के कमजोर, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों जो समस्याओं से संबंधित विभागों एवं अदालतों तक नहीं पहुंच पाते हैं और अपना हक हुकूक हासिल न होने से भाग्य को दोषी मानकर समस्या से पीड़ित रहते हैं उनको न्याय दिलाने के लिए यह संस्थान निस्वार्थ भाव से कार्य करेगी। इन सुविधाओं को प्रभावी बनाने के लिए संस्थान उचित लोगों का चयन करेगी जो स्वेच्छा से समाज में आमूल - चूल परिवर्तन के प्रणेता के रूप में कार्य करने को तैयार हैं। विधिक कार्यवाही हो या मानवाधिकार मूल्य हो, सामाजिक समरसता के लिए संस्थान की तरफ से निशुल्क एडवोकेट नियुक्त किए जाएंगे जिनका खर्च संस्थान एवं पदाधिकारी उठाएंगे। संस्थान का प्रमुख उद्देश्य है कि भारत को समृद्ध व मजबूत बनाने की अवधारणा, भ्रष्टाचार मुक्त उन्नत समाज की परिकल्पना, समाज में आर्थिक रूप से कमजोर दलित पिछड़े अल्पसंख्यक महिला एवं पुरुष, जो पीड़ित हैं उनके अधिकारों को दिलाना।

समाज को नई दिशा देने के लिए युवाओं को उचित मार्गदर्शन तथा रोजगार उन्मुख कार्यशाला का आयोजन कर प्रेरित करना। रोजगार परक ट्रेनिंग देकर स्टार्टअप जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को आत्म निर्भर बनाने का कार्य संस्था करेगी। वर्तमान समय में आम आदमी को शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य की मूलभूत आवश्यकता है। उसकी उपयोगिता उपलब्ध कराने हेतु सुनिश्चित करना, समान नागरिक संहिता लागू कराने का प्रयास प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। एक भारत, श्रेष्ठ भारत, सब का साथ, सबका विकास की सोच रखने वाले प्रधानमंत्री की नीतियों को जन तक पहुंचाने के लिए संस्थान वचनबद्ध है। भारत में आजादी के बाद भी किसान वर्ग सबसे ज्यादा उपेक्षित रहा है, उसके कल्याण के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को सुनिश्चित करने के अलावा केवल कृषि पर निर्भर रहने वाले किसानों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का मजबूत प्रयास किया जाएगा। हर खांटी किसान परिवार के एक सदस्य को नौकरी तथा मेडिकल, इंजीनियरिंग इत्यादि कालेजों में पढ़ाई मुफ्त कराने की कोशिश संस्थान करेगी।



“स्वतंत्रता एवं न्याय प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार”

केन्द्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान



www.cpgii.org

द्वारा आयोजित



chairmancpgi@gmail.com

आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर भारत अमृत घोषणा के शुभ अवसर पर



केन्द्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान



राष्ट्र गौरव सम्मान

लोक शिकायत एवं निराकरण विषयक संगोष्ठी

सम्मानित होने वाले अति विशिष्ट अतिथियां

कार्यक्रम स्थल - उम्प्र० उर्दू अकादमी सभागार, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

दिनांक - 16 जुलाई 2022, दिन - शनिवार, समय - दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक



गोपाल राय
प्रबन्धन C.P.G.I.
मो. 9306016178





2ND JUSTICE DIPAK MISRA NATIONAL MOOT COURT COMPETITION, 2021-22

Patron-in-Chief

Hon'ble Mr. Justice Dipak Misra
Former Chief Justice of India

Patrons:

Mr. Vivek Narayan Sharma
Ex-Joint Secretary, SCAOR Association

Mr. Ashwani Dubey
AoR, Supreme Court of India

Mr. Satish Kumar
AoR, Supreme Court of India

Mr. Bhagyodaya Mishra
Advocate, Gujarat High Court &
Supreme Court of India

Academic Administrator
Prof. Shashank Shekhar
Assistant Professor, NLU Jodhpur

Mooting Administrator
Mr. Aman Kumar
Senior Associate, The Advocates League

Managing Administrator
Mr. Nitish Kumar Mishra
Convenor, The Advocates League

General Administrator
Mr. Ashish Kumar Rai
President, The Advocates League

Program Administrator
Mr. Johns Santhosh
Secretary, The Advocates League

Executive Coordinator
Mr. Shubham Kumar
Vice President, The Advocates League

Chairman, Steering Committee
Mr. Abhishek Jaiswal
Co-Convenor, The Advocates League

Organizing Secretary
Mr. Shashwat Tripathi
Admin Head, The Advocates League

Joint Organizing Secretary
Mr. Anubhav Mishra
Academic Head, The Advocates League

Chief Coordinators
Mr. Om Singhania
Joint Academic Head, TAL
Mr. Alpesh Kumar
Deputy Chief Operating Officer, TAL
Mr. Amish Tiwari
Special Director, Department of Criminal Law

Coordinators
Mr. Gopal Krishna
Director, Department of ADR
Ms. Riya Luhadia
Director, Department of Criminal Law

Ref. No.-TAL/02(e)/12795

Date - 09-07-2022

APPRECIATION NOTE

The idea of redressing the Public Grievances through Non Government Office under the umbrella of Central Public Grievances & Investigation Institute is a great initiative by the Social Workers.

We wish all the best to all the office holders for doing such an exemplary work.

Yours Sincerely,

Justice Dipak Misra

Hon'ble Mr. Justice Dipak Misra
Former Chief Justice of India

To,
Shri. Gopal Rai
National President, CPGII
65/25, Chitwapur Road, Lalkuhan,
Lucknow, Uttar Pradesh



भगत सिंह कोश्यारी

राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य



राज भवन

मलबार हिल

मुंबई ४०० ०३५

दूरध्वनी : ०२२-२३६३ २६६०

फैक्स : ०२२-२३६८ ०५०५

शुभकामना

१६ जून २०२२

केन्द्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान (रजि) द्वारा माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्र गौरव सम्मान, लोक शिकायत व निराकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं इस संबंध में स्मारिका का प्रकाशन/विमोचन हेतु भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अत्यंत प्रसन्नता हुई।

संस्थान विगत कई वर्षों से जिस प्रकार मानवीय व राष्ट्रीय कार्यों विशेषतः नागरिकों के अधिकार, न्याय एवं समस्त मूलभूत आवश्यकतों हेतु प्रयासरत है। निश्चित ही समाज में इन कार्यों से न सिर्फ जागरूकता का संचार होगा बल्कि शिष्ट व श्रेष्ठ भारत के निर्माण की ओर अग्रसर होंगे।

संस्थान के मार्गदर्शन से वंचित, दलित, पिछड़े, महिला, बच्चे, पीड़ितों एवं अल्पसंख्यक समाज को लाभ होगा। ऐसी आशा व कामना करता हूँ।

अतः इस सामाजिक व राष्ट्रीय कार्य हेतु संस्थान से संबंधित समस्त विद्वत् पदाधिकारीगण व संरक्षक मण्डल के महानुभावों को हार्दिक शुभकामनाएं।

धन्यवाद।

भवदीय

(भगत सिंह कोश्यारी)
राज्यपाल, महाराष्ट्र

श्री गोपाल राय

मा. अध्यक्ष

६५/२५ छितवापुर रोड़,
लाल कुआँ, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश-२२६००९

पुष्कर सिंह धामी



मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सचिवालय

देहरादून— 248001

0135—2716262

0135—2650433

फैक्स: 0135—2712827

विधान सभा फोन: 0135—2665100

0135—2665497

फैक्स: 0135—2666166

Email: cm-ua@nic.in

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि केन्द्रीय लोक शिकायत एवं जाँच संस्थान द्वारा स्वतंत्रता के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में संस्थान के तत्वावधान में समग्र विचार प्रवाह लोक शिकायत निराकरण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन एवं स्मारिका का विमोचन किया जा रहा है।

मुझे आशा ही नहीं वरन् पूर्ण विश्वास है कि उक्त स्मारिका में देश को समृद्ध एवं मजबूत बनाने, भ्रष्टाचार मुक्त उन्नत समाज की परिकल्पना एवं समाज में आर्थिक रूप से कमज़ोर, दलित, पिछड़े वर्ग, युवाओं को मार्गदर्शन तथा संस्थान द्वारा समाज हित में किये गये उत्कृष्ट कार्यों का समावेश होगा, जो निश्चित रूप से समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए अत्यन्त प्रेरणादायी सिद्ध होगा। संस्थान द्वारा किये गये राष्ट्रहित में ऐसे महान कार्यों को एक स्मारिका के माध्यम से प्रकाशित किया जाना निःसंदेह प्रशंसनीय कार्य है।

मेरी ओर से संस्थान को स्वतंत्रता के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्मारिका के विमोचन हेतु हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

(पुष्कर सिंह धामी)

श्री गोपाल राय जी,
राष्ट्रीय अध्यक्ष,
केन्द्रीय लोक शिकायत एवं जाँच संस्थान,
प्रशासनिक कार्यालय 65 / 25, छितवापुर रोड़,
लालकुआँ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

ब्रजेश पाठक

उप मुख्यमंत्री



चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,
परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु
कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय कम संख्या-99, 100, मुख्य भवन,
विधान सभा सचिवालय

दूरभाष- 0522-2238088/2213272 (का)

लखनऊ: दिनांक 01/07/2022

शुभकामना संदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि केन्द्रीय लोक शिकायत एवं जॉच संस्थान (रजि.) द्वारा माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्र गौरव सम्मान, लोक शिकायत व निराकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं स्मारिका का प्रकाशन हेतु भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

संस्थान विगत कई वर्षों से जिस प्रकार मानवीय व राष्ट्रीय कार्यों विशेषतः नागरिकों के अधिकार न्याय व समस्त मूलभूत आवश्यकताओं हेतु प्रयासरत है। निश्चित ही समाज में इन कार्यों से न सिर्फ जागरूकता का संचार होगा बल्कि शिष्ट व श्रेष्ठ भारत का निर्माण की ओर अग्रसर होंगे।

मैं साथ ही ऐसी आशा करता हूँ कि संस्थान के मार्गदर्शन से वंचित, पिछड़े, महिला, बच्चे, पीड़ितों एवं अल्पसंख्यक समाज को लाभ होगा।

मैं इस स्मारिका के प्रकाशन एवं कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

(ब्रजेश पाठक)

एस० एन० साबत,
आई.पी.एस.



पुलिस महानिदेशक (सतर्कता)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड,
शक्तिभवन, लखनऊ
फोन नं० ०५२२-२२८७८७५ (कार्यालय)
०५२२-२२८७८५५ (फैक्स)
दिनांक: जुलाई ६, २०२२

सन्देश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता है कि स्वतन्त्रता के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में लोक शिकायत निराकरण विषय पर केन्द्रीय शिकायत एवं जॉच संस्थान द्वारा कार्यक्रम का आयोजन एवं स्मारिका का विमोचन किया जा रहा है।

मुझे विश्वास है कि इस स्मारिका में राष्ट्रीय हित में किये गये उत्कृष्ट कार्यों का समावेश किया जायेगा, जो समाज के प्रत्येक वर्ग के लिये प्रेरणादायी सिद्ध होगा। संस्थान का यह कार्य प्रशंसनीय है। इस अवसर पर संस्थान को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें हैं।

संसदगांव,

भवदीय,

(एस०एन० साबत्)

श्री गोपाल राय,
राष्ट्रीय लोक शिकायत एवं जॉच संस्थान
प्रशासनिक कार्यालय ६५/२५, छितवापुर रोड
लालकुओँ लखनऊ।

मंजीव कुमार शुक्ल



पत्रोंक: //109



डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल,
होमगार्डम पश्चिम परिक्षेत्र,
आगरा।

सीयूजी नं 0-8005194091,
ईमेल आईडी 0-dycg-hg.ag@up.gov.in
दिनांक जुलाई // ,2022

प्रिय महोदय,

शुभकामना सन्देश

मुझे यह जानकार अत्यन्त प्रमाणित है कि स्वतन्त्रता के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में लोक शिकायत निगरण विषय पर केन्द्रीय शिकायत एवं जाँच मंस्थान द्वारा कार्यक्रम का आयोजन एवं स्मारिका का विमोचन किया जा रहा है।

मुझे विश्वास है कि इस स्मारिका में राष्ट्रीय हित में किये गये उन्नत कार्यों का समावेश किया जायेगा, जो समाज के प्रत्येक वर्ग के लिये प्रेरणादायी मिद्ध होगा। मंस्थान का यह कार्य प्रशंसनीय है। इस अवसर पर मंस्थान को मेरी हार्दिक वधाई एवं शुभकामनायें हैं।

समृद्धभाव

भवदीय

MM
11. 07. 2022
(मंजीव कुमार शुक्ल)

श्री गोपाल राय,

राष्ट्रीय लोक शिकायत एवं जाँच मंस्थान,
प्रशासनिक कार्यालय 65/25, द्वितीयापुर रोड,
नालकुओं, लखनऊ।

डा० राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।



विधान भवन,
लखनऊ।
दिनांक: 01 जुलाई, 2022

समान नागरिक संहिता की आवश्यकता एवं विधिक विवेचना



समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग-4 राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद-44 में वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद-44 के अनुसार राज्य सम्पूर्ण देश में 'समान नागरिक संहिता' लागू करने का प्रयास करेगा अर्थात् सभी के लिए निजी कानून एक जैसे होंगे, निजी कानूनों से अभिप्राय ऐसे कानूनों से है जो निजी मामलों में लागू होते हैं, जैसे— विवाह, तलाक एवं उत्तराधिकार।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के माध्यम से 'पंथ निरपेक्ष' शब्द को प्रविष्ट किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य भारत के समस्त नागरिकों के साथ धार्मिक आधार पर किसी भी भेद-भाव को समाप्त करना है।

मूल अधिकारों में 'विधि के शासन' का उल्लेख है, जिसके अनुसार सभी नागरिकों हेतु एक समान विधि होनी चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी समान नागरिक संहिता का लागू न होना एक प्रकार से विधि के शासन और संविधान के प्रस्तावना का उल्लंघन है।

भारत में अलग-अलग धर्मों में विवाह, तलाक एवं उत्तराधिकार से सम्बद्धित अलग-अलग विधान हैं। कुछ धर्मों में प्रचलित कुरीतियों एवं रुद्धियों के खिलाफ लम्बे आन्दोलन चले हैं, लेकिन कुछ धर्मों के विभिन्न समुदायों में आज भी ऐसे निजी कानून प्रचलित हैं जो मानवीय गरिमा का अपमान करते हैं और समतामूलक समाज के निर्माण में बाधक बनते हैं।

इसलिए पंथ निरपेक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य को धर्म आधारित कानूनों पर युक्ति-युक्त परिवर्तन लगाकर भारत के समस्त नगरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता बनी हुयी है। भारत सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जुलाई, 2019 में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कानून बनाया है जिसके द्वारा तीन तलाक को गैर कानूनी घोषित दिया गया है एवं दण्ड का भी प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में भारत सरकार ने अगस्त, 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटा दिया है।

समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर संविधान सभा में बोलते हुए डा० भीमराव आंबेडकर ने कहा था कि "हमारे देश में मानवीय सम्बन्धों के प्रायः प्रत्येक पहलू को प्रभावित करने वाले कानूनों की एक समान दंड संहिता है, जो 'भारतीय दंड संहिता' एवं 'अपराध दंड संहिता' में निहित है। वर्तमान समय में ऐसे बहुत से कानून हैं जो देश के नगरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं लेकिन विवाह एवं उत्तराधिकार के कानून अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग होने की वजह से प्रायः ये नागरिक अधिकारों का हनन करते नजर आते हैं। महिलाओं को इन कानूनों से सबसे अधिक नकारात्मक तौर पर प्रभावित होना पड़ता है।" "संविधान सभा में मीनू मसानी, हंसा मेहता एवं राजकुमारी अमृत कौर ने समान नागरिक संहिता को मूल अधिकारों के तहत रखने की वकालत की थी। संविधान सभा में बहस के दौरान कुछ सदस्यों ने आशंका प्रकट की थी कि यह मुस्लिमों के विरुद्ध है लेकिन इस आशंका को निर्मूल करार देते हुए डा० आंबेडकर ने कहा था कि "मेरा दृढ़ विश्वास है कि मुस्लिमों को कभी भी यह कहने का अवसर नहीं मिलेगा कि समान नागरिक संहिता के निर्माताओं ने मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आधात पहुँचाया है।"

सर्वोच्च न्यायालय से समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए अब तक तीन बार केन्द्र को दिशा-निर्देश दिया है। सबसे प्रसिद्ध निर्णय 'मुहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम' वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1985 में अपना निर्णय देते हुए कहा था कि 'यह अत्यंत खेद की बात है कि संविधान का अनुच्छेद-44 अभी तक लागू नहीं

किया गया और सरकार की ओर से इसे संसद द्वारा पारित कराने का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। जबकि तत्कालीन सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ संसद में मुस्लिमों के निजी कानूनों के हित में विधेयक पास करवाया। दूसरी बार 'सरला मुदगल बनाम भारत सरकार' वाद में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता की अनिवार्यता की बात कही। साथ ही यह भी कहा कि अनुच्छेद-25, 26 एवं 27 (धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार) में दिये गए मूल अधिकार का हनन नहीं करता। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय ने 'जार्डन डिंग डोह बनाम स्वरनजीत सिंह चोपड़ा' वाद एवं 'जान वल्ला मैट्टम बनाम भारत सरकार' के वाद में भी समान नागरिक संहिता के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि "ऐसे समय में जब महिलाएं अपने अधिकारों और अपनी निजता को लेकर सजग हो रहीं हैं तो समान नागरिक संहिता की बात करना किन्हीं धार्मिक निजी कानूनों की तुलना में अधिक प्रगतिशील एवं लोकतांत्रिक है।" लिली थामस केस में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता पर बल दिया है।

भारतीय लोकतंत्र में अभी भी यह अभीष्ट है कि समान नागरिक संहिता इस प्रकार लागू हो जिसमें विभिन्न धर्मावलम्बियों तथा विभिन्न धर्मों के पुरुषों तथा स्त्रियों के मध्य कोई विभेद न हो। समान नागरिक संहिता इन देशों में लागू है जैसे बिट्रेन, अमेरिका, फ्रान्स और आस्ट्रेलिया, यहाँ तक मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य तुर्की एवं मिस्र (इजिप्ट) में भी समान नागरिक संहिता लागू है। गोवा में 1962 से लागू समान नागरिक संहिता, पुर्तगाली समान नागरिक संहिता, 1867 के तहत लागू किया गया है, जो उत्तराधिकार और विरासत के अधिकारों को संचालित करता है। इसमें बहुविवाह पर भी प्रतिबन्ध है। समान नागरिक संहिता के लागू होने से अलग—अलग धर्मों के अलग—अलग कानून से न्यायपालिका पर पड़ने वाला बोझ भी कम होगा और न्यायालयों में वर्षों से लम्बित पड़े मामलों के निर्णय शीघ्र होंगे। सभी के लिए एक समान कानून लागू होने से देश में एकता और बन्धुता को बढ़ावा मिलेगा और कानून के स्तर पर किसी प्रकार की वैमनस्यता नहीं होगी, ऐसे सकारात्मक माहौल में देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। देश में एक समान कानून लागू होने से देश का राजनैतिक माहौल भी बदलेगा और राजनीतिक दलों द्वारा वोट बैंक वाली राजनीति से जनता को छुटकारा मिलेगा। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आयेगा। अभी भी कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। समान नागरिक संहिता लागू हो जाने से पूरे देश में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे सामाजिक मुद्दे एक समान कानून के अन्तर्गत आ जायेंगे और धर्म के आधार पर कोई अलग व्यवस्था नहीं होगी। धार्मिक रुद्धियों की वजह से समाज के किसी वर्ग के अधिकारों का हनन रोका जाना चाहिए साथ ही 'विधि के समक्ष समता' की अवधारणा के तहत सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। वैश्वीकरण के वातावरण में महिलाओं की भूमिका समाज में महत्वपूर्ण हो गई है, इसलिए उनके अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता में किसी प्रकार की कमी उनके व्यक्तित्व तथा समाज के लिए अहितकर है।

विधिक प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकार समान नागरिक संहिता के सम्बन्ध में विधि निर्माण कर सकती है अथवा नहीं? निःसंदेह समान नागरिक संहिता राज्य विधान मंडल द्वारा अधिनिर्मित किया जा सकता है परन्तु विचारणीय प्रश्न यह है कि सरीयत एक्ट 1939 एवं अन्य धर्म मानने वालों से सम्बन्धित अन्य अधिनियम केन्द्र सरकार द्वारा अधिनिर्मित हैं। इसके अतिरिक्त हिन्दू कोड बिल भी केन्द्र सराकर द्वारा अधिनिर्मित है। यदि राज्य सरकार द्वारा यूनिफार्म सिविल कोड बनाया जाता है तो उपरोक्त केन्द्रीय विधियों में कतिपय संशोधन करना पड़ेगा। जिसके लिये महामहिम राश्ट्रपति महोदय की अनुशंशा आवश्यक होगी परन्तु समान नागरिक संहिता देश के लिये परम आवश्यक है यथाशीघ्र इस सम्बन्ध में विधि निर्मित की जानी चाहिये।

जय हिन्द !

श्री गोपाल राय जी,
राष्ट्रीय अध्यक्ष,
केन्द्रीय लोक शिकायत एवं जाँच संस्थान,
प्रशासनिक कार्यालय 65/25, छितवापुर रोड़,
लालकुआँ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

डा० राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव, विधान परिषद्
उत्तर प्रदेश।

दानिश आज़ाद अंसारी

राज्य मंत्री

अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम
वक्फ एवं हज।



कार्यालय कक्ष सं0: जी-2/3

बापू भवन, उ0प्र0 सचिवालय,
लखनऊ

दूरभाष कार्यालय: 0522-2239277

सी0एच0: 0522-2214796

फैला. 295 / बैठाईपौर/समा०/उत्तर प्रदेश, मुज़फ्फरगढ़ एवं हज/20
दिनांक 07.07.2022

दिनांक: 07 जुलाई, 2022

प्रिय महोदय,

केन्द्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान (रजि) द्वारा माननीय प्रधानमंत्री
राष्ट्र गौरव सम्मान, लोक शिकायत व निराकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं इस
संबंध में स्मारिका का प्रकाशन/विमोचन हेतु भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया
जा रहा है। अत्यंत प्रसन्नता हुई।

संस्थान विगत कई वर्षों से जिस प्रकार मानवीय व राष्ट्रीय कार्यों विशेषतः
नागरिकों के अधिकार, न्याय एवं समस्त मूलभूत आवश्यकताओं हेतु प्रयासरत है।
निश्चित ही समाज में इन कार्यों से न सिर्फ जागरूकता का संचार होगा बल्कि
शिष्ट व श्रेष्ठ भारत के निर्माण की ओर अग्रसर होंगे।

संस्थान के मार्गदर्शन से वंचित, दलित, पिछड़े, महिला, बच्चे, पीड़ितों एवं
अल्पसंख्यक समाज को लाभ होगा, ऐसी आशा व कामना करता हूँ।

अतः इस सामाजिक व राष्ट्रीय कार्य हेतु संस्थान से संबंधित समस्त विद्वत
पदाधिकारीगण व संरक्षक मण्डल के महानुभावों को हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीय,

(दानिश आज़ाद अंसारी)

श्री गोपाल राय,
राष्ट्रीय अध्यक्ष,
केन्द्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान,
65 / 25 छितवापुर रोड, लालकुआँ,
लखनऊ-226001

फोन नं. : +91-8881101103, 6386414503

Mob : +91-8881101103, 6386414503

S.Aithar Sagheer Zaidi "Turai Zaidi"
Chairman

Fakhruddin Ali Ahmad Memorial Committee
(U.P. GOVT.)

राज्य सरकार द्वारा संभालित करने वाली
कल्पना दीन अधिकारी एवं समाज का सदस्य

कल्पना दीन अधिकारी एवं समाज का सदस्य

प्रबन्धन का नाम है।



Ref No: 106186

Date: 07-07-2022

इनकामना सन्देश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि केन्द्रीय लोक शिकायत एवं जीव संस्थान (रजिस) द्वारा मानवीय प्रचानमन्त्री राहुल गोद्य समान, लोक शिकायत एवं निराकरण पर राष्ट्रीय संगठनी एवं स्मारिका का प्रकाशन हेतु भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

संस्थान विगत कई वर्षों से निस प्रकार मानवीय एवं राष्ट्रीय कार्यों विशेषतः नागरिकों के अधिकार नियाय य समासून्त आवश्यकताओं हेतु प्रयत्नत है। निश्चित ही समाज में इन कार्यों से न सिर्फ जागरूकता का सचार होगा बल्कि विहृत व श्रेष्ठ भारत के निर्माण की ओर अप्रसर होगे।

मैं सच्च ही ऐसी आशा करता हूँ कि संस्थान के मानवरक्षण से योचित, पिछड़े, महिला, बच्चे, परिवार एवं अवसरकृत समाज को लाभ होगा। ऐसी आशा ये कामों के हेतु।

मैं इस स्मारिका के प्रकाशन एवं कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु हार्दिक शुभकामनाएँ।

श्री गोपाल राध,

मानवीय अध्यक्ष,
65/25 छिनवापुरोड,
लालकुआं, लखनऊ-226001।

Haider Abbas Chand
Member, U.P. Commission for Minorities
(सौ अताहर सारीर जैदी-तूरज जैदी)

उत्तर संख्यक आयोग U.P. Commission for Minorities



राज्य सरकार द्वारा संभालित करने वाली
कल्पना दीन अधिकारी एवं समाज का सदस्य

Lucknow Office:
504, India Bhawan, Lucknow-1
Mob: 9454660786, 9451196786
E-mail: chaitbjp@gmail.com
Post: C-1860, Mata Kund, Lalitpura, Varanasi



Haider Abbas Chand
Member
हैदर अक्बास चौटा
सदस्य

शुभकामना-संदेश

केन्द्रीय लोक शिकायत एवं जीव संस्थान प्रबन्धनमन्त्री राहुल गोद्य समाज और संस्थान का नियोजन पर राष्ट्रीय संघीय एवं इस संबंध में स्थानिकों का व्यक्तिगत विवेदन है।

ऐसे व्यक्ति विवेदन कर्त्ता के अधिकार का अयोजन किया जा रहा है। अन्यत्र प्रसन्नता है।

संस्थान विगत कई वर्षों से निस प्रकार मानवीय एवं राष्ट्रीय कार्यों विशेषतः नागरिकों के

अधिकार, व्यावहारिक समस्त मूलभूत आवश्यकताओं हेतु प्रयत्नत है। निश्चित ही समाज में इन

कार्यों से न सिर्फ जागरूकता का सचार होगा बल्कि विहृत व श्रेष्ठ भारत के निर्माण की ओर अप्रसर होगा।

संस्थान के पार्श्वान से विविध शिक्षित, प्रिज़्डे, महिला, बच्चे, परिवार एवं अवसरकृत

समाज को लाभ होगा। ऐसी आशा ये कामों के हेतु।

अतः समाजिक एवं राष्ट्रीय कार्यों हेतु संस्थान से समर्पित मामल विद्वत प्राप्तिकारीण व

संस्थान के मानवान्तरों को हार्दिक शुभकामनाएँ।

धन्यवाद।

Haider Abbas Chand
Member
(हैदर अक्बास चौटा)

सदस्य

श्री गोपाल राध,
मानवीय अध्यक्ष,

65/25 छिनवापुरोड,
लालकुआं, लखनऊ-226001।

प्रेषक,

सचिव,
लोक आयुक्त, उ०प्र०,
लखनऊ।

सेवा में

श्री गोपाल राय,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय लोक शिकायत एवं जाँच संस्थान,
प्रधान कार्यालय-65 / 25, छितवापुर रोड,
लालकुआँ, जिला-लखनऊ।
पिन कोड 226001

लोक आयुक्त

उत्तर प्रदेश



पोस्ट बॉक्स नं०: 172 (जी.पी.ओ.)
टी०सी०-४६/वी-१, विभूति खण्ड,
गोमती नगर,
लखनऊ-२२६ ०१०
दूरभाष: २७२८६६०
: २३०६०८८
: २३०६७१७
फैक्स: (०५२२)२३०६६४७

संख्या-746-2022/02/ 5391
विषय- आप द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संबंध में।

दिनांक 28 जून, 2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र दिनांक 11.06.2022 के क्रम में सूचित करना है कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 9(5) के अन्तर्गत माननीय लोक आयुक्त जी द्वारा प्रकरण को समाप्त कर दिया गया है। साथ ही सूचना पुस्तिका संलग्न कर प्रेषित करते हुए यह भी सूचित करना है कि यदि आप किसी लोक सेवक के विरुद्ध अभिकथन रूपी परिवाद अथवा शिकायत रूपी परिवादी करना चाहते हैं, तो संलग्न सूचना पुस्तिका के अनुसार नियमित परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं।

लोक आयुक्त प्रशासन में परिवाद दाखिल करने संबंधी जानकारी हेतु सूचना पुस्तिका संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। साथ यह भी अवगत करना है की इस प्रशासन में परिवाद सूचना पुस्तिका में दिये गये प्रारूप पर तीन प्रतियों में प्रस्तुत किये जाते हैं और परिवाद एवं संलग्नकों को परिवादी के द्वारा उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 तथा धारा 9(3) के अनुसार सत्यापित करना होता है तथा परिवाद एवं उसके साथ संलग्नकों के सम्बन्ध में एक नोटरी सप्त पत्र परिवादी का एवं उन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों का भी शपथ पत्र उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 तथा धारा 9(2) के अनुसार देना होता है, जिनसे तथ्यों के बारे में जानकारी होने का परिवाद में उल्लेख हो। परिवादी को अपना पूरा पता, मोबाइल नम्बर तथा ई०मेल आई०डी० यदि हो तो अकित करना होता है।

इस सम्बन्ध में आपको यह भी अवगत करना है कि परिवाद दो तरह के होते हैं पहला शिकायत दूसरा अभिकथन। अभिकथन रूपी परिवाद के साथ दो हजार रुपये प्रतिभूति कोषागार में जमा की जाती है। और इस स्थिति में दो हजार रुपये प्रतिभूति जमा करते हुये चालान की मूल प्रति इस प्रशासन में उपलब्ध कराने के साथ ही साथ परिवादी को अपने राष्ट्रीकृत बैंक का बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा का नाम, बैंक का आई०एफ०एस०सी० कोड, संबंधित जिले का नाम एवं स्व-प्रमाणित बैंक पासबुक की फोटोकॉपी भी इस प्रशासन को उपलब्ध करानी होती है। जिससे यथास्थिति प्रतिभूति की धनराशि ई-पेमेन्ट के माध्यम से आपके खाते में स्थानान्तरित करायी जा सके।

संलग्नक- सूचना पुस्तिका।

महोदय
27/6/22
कृत सचिव

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम 1975 की धारा 9(3) के अनुसार सत्यापन निम्न ढंग से किया जा सकता है। सत्यापन न होने पर सामान्यता परिवाद ग्रहण न किया जा सकेगा।

सत्यापन

परिवाद में पैरा- 1 से लगायत 12 में लिखित बातें एवं परिवाद के साथ संलग्न प्रपत्र मेरी जानकारी में पूर्णतया सही है तथा जिनके सही होने का विश्वास करता हूँ। तदनुसार परिवाद पत्र एवं संलग्नकों को सत्यापित किया जाता है।

दिनांक
स्थान

सत्यापनकर्ता
परिवादी का हस्ताक्षर/ नाम/पता/ मोबाइल नं० सहित

लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश



~~कुप्रशासन~~

~~भष्टाचार~~

प्रदेश को भष्टाचार/कुप्रशासन मुक्त बनाने हेतु जनता से अपील

मंत्रियों, विधायकों व अन्य लोकसेवकों के विरुद्ध भष्टाचार, पद के दुरुपयोग व कुप्रशासन के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले परिवादों (अभिकथन / शिकायत) को ग्रहण करके लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के द्वारा उसका निराकरण करते हुए उत्तरदायी मंत्रियों, विधायकों और लोकसेवकों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु संस्तुतियाँ सक्षम प्राधिकारी (मुख्यमंत्री / मुख्य सचिव) को प्रेषित की जाती है और वार्षिक प्रतिवेदन माननीय श्री राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

अधिकारिता

उत्तर प्रदेश शासन के समस्त विभाग, सरकारी कम्पनियाँ, सहायक सरकारी कम्पनियाँ, निगम, सोसाइटीज व परिषदें (जो अनुसूचित की गई हों) से संबंधित परिवादों (अभिकथन / शिकायत) के मामलें तथा सेवानिवृत्त देयकों के भुगतान, मृतक आश्रित सेवायोजन, विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद, निराश्रित एवं वृद्ध महिलाओं के पेंशन, अनुसूचित जाति व जनजातियों के आरक्षण (सेवा) संबंधी मामले।

उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त अधिकारीगण (धारा-22 में वर्णित न्यायाधीश / न्यायिक अधिकारी, महालेखाकार आदि को छोड़कर) एवं कर्मचारियों के साथ-साथ मंत्रीगण (मुख्यमंत्री को छोड़कर), विधायक, विधान परिषद सदस्य, महापौर महापालिका, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों तथा अध्यक्ष, जिला पंचायत (ग्राम प्रधान को छोड़कर) भी सम्मिलित हैं के विरुद्ध परिवाद (अभिकथन / शिकायत)। शासकीय लोक सेवकों के सेवानिवृत्त / सेवाकाल में मृत्यु से संबंधित देयकों के प्रकरण से संबंधित परिवाद जो कि शिकायत की श्रेणी में आते हैं प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

अभिकथन/शिकायत की प्रक्रिया

प्रदेश के लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त को अभिकथन तथा शिकायत सम्बन्धी परिवाद निर्धारित प्रपत्र पर तीन प्रतियों में (यथासंभव राजभाषा हिन्दी में) अंकित कराकर धारा-9(2) के अनुसार नोटरी शपथ पत्र एवं धारा-9(3) के अनुसार परिवाद, शपथ पत्र, संलग्नक / अनुलग्नक का सत्यापन परिवादी स्वयं के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करके एवं अभिकथन रूपी परिवादों में रु 2,000/- प्रतिभूति निर्धारित लेखा शीर्षक "8443 सिविल निक्षेप-00-103-प्रतिभूति निक्षेप-00-00" के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक अथवा कोषागार में चालान के माध्यम से जमा करके मूलप्रति सहित प्रस्तुत किया जा सकता है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि प्राप्त परिवाद मिथ्या / फर्जी पाया जाता है तो ऐसे परिवादियों पर माननीय लोक आयुक्त द्वारा रु 50,000/- तक की धनराशि का हर्जाना लगाया जा सकता है एवं प्रतिभूति की धनराशि जब्त की जा सकती है।

नोट- राज्य सरकार द्वारा ई-पेमेन्ट से भुगतान किये जाने के कारण, परिवादी अपना राष्ट्रीयकृत बैंक का बचत खाता संख्या, बैंक व शाखा का नाम, जिला एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड के साथ-साथ पासबुक की स्वप्रमाणित छायाप्रति, परिवाद दाखिल करते समय प्रतिभूति की धनराशि के मूल चालान के साथ उपलब्ध करायेंगे तभी उनको प्रतिभूति की धनराशि वापस किया जाना सम्भव होगा। परिवादी को अपना पूरा नाम, पता, मोबाइल नम्बर / ई-मेल के साथ अंकित करना चाहिए।

सचिव, लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

वर्तमान पता - टी0सी0-46 / वी-1 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 अथवा
पोर्ट बाक्स नम्बर-172, जी0पी0ओ0, लखनऊ।

फोन नं0 - (0522) 2728660, 2306717, 2728865, 2306088, 2306160(पी0वी0 एक्स), 2306412

फैक्स नं0 - (0522) 2306647

Web Site - www.lokayukta.up.nic.in E-mail :- lokayukta@hotmail.com

आर0एन0 पाण्डेय एच0जे0एस0

सचिव



PARIJAAT
INFRAESTATE PVT. LTD.

दिनांक 11/07/22

सन्देश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता है कि स्वतन्त्रता के 75 वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में लोक शिकायत निराकरण विषय में केन्द्रीय शिकायत एवं जॉच संस्थान द्वारा कार्यक्रम का आयोजन एवं स्मारिका का विमोचन किया जा रहा है।

मुझे तिश्लास है कि इस स्मारिका में राष्ट्रीय हित में किये गये उत्कृष्ट कार्यों का समावेश किया जायेगा, जो समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रेरणादायी सिद्ध होगा।

संस्थान का यह कार्य प्रशंसनीय है। इस शुभ अवसर पर संस्थान को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाये।

Parijaat Infraestate Pvt. Ltd.

आपका

Director

धन्यवाद

बाकर अम्मार नक्ती (हसन)

श्री गोपाल राय जी

डायरेक्टर पारिजात इन्फ्रास्टेट प्रा. लि.

राष्ट्रीय लोक शिकायत एवं जॉच संस्थान

लखनऊ

प्रशासनिक कार्यालय 65/25 छितवा पुर रोड

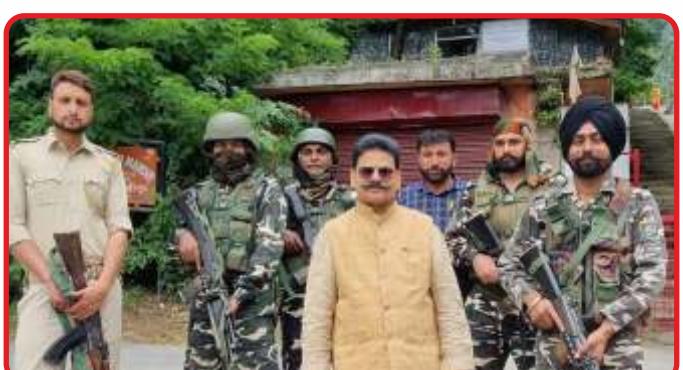
सम्पर्क: 6306031325

लालकुआं लखनऊ

PARIJAAT INFRAESTATE PVT. LTD.

Corporate Office : D-3/91, Vijyant Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Website : www.parijaatinfra.in | Phone : 0522-4323148 | Mob. : 6306031325









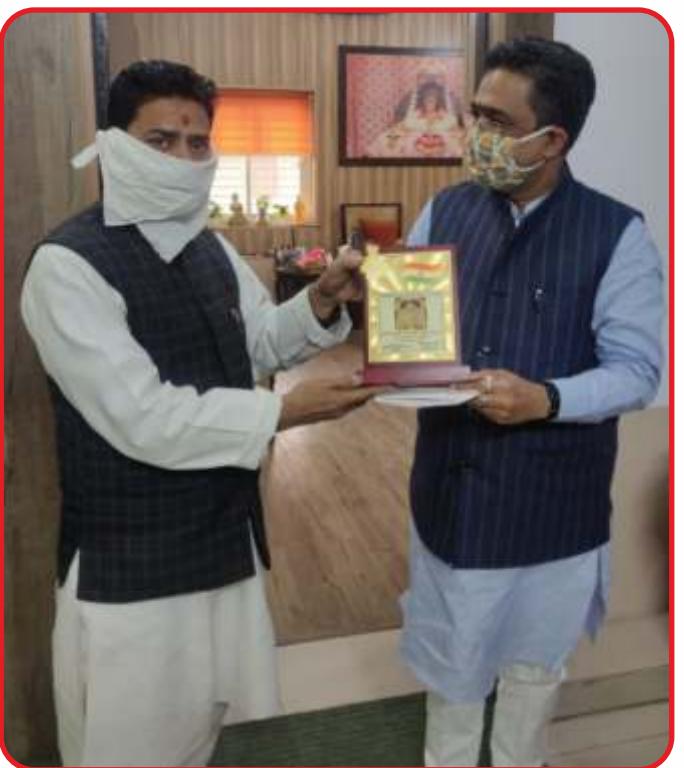




















PARIJAAT
INFRAESTATE PVT. LTD.



Parijaat
Residency

Lucknow-Ayodhya Highway (NH-28)



PARIJAAT RESIDENCY

लखनऊ- अयोध्या (NH-28) में हाइवे पर
सागर इंस्टिट्यूट और जयपुरिया कॉलेज के पास
आवासीय एवं कमर्शियल प्लॉट

50% धनराशि देकर पाये,
बैंकद्वारा काजा दालिन रासिङ, शेष आसान वित्तीय पर ब्याज रहित

बुकिंग मात्र ₹50,000 से
Plot At ₹550 - ₹700/- sq.ft

COMMERCIAL PLOTS ALSO AVAILABLE



PARIJAAT INFRAESTATE PVT. LTD.

Corporate office : D-3/91, Vijay Khand, Gomti Nagar, Lucknow- 226010
website : www.parijaatinfra.in | Phone : 0522-4323148 | Mob.: 6306031325